



कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिये स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है।

-ब्रह्माकुमारी शिवानी

जिद...सच की

● वर्ष: 11 ● अंक: 186 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार 11 अगस्त, 2025

एशिया कप: भारतीय ओपनिंग पर... 7 बांग्लादेशी या बहाना? सिर्फ मुसलमान... 3 योगी ने भी यूपी में लूटा है... 2

वोट चोरी व एसआईआर को लेकर विपक्ष का जोरदार हल्ला बोल

कांग्रेस-सपा समेत सभी दलों ने निकाला चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च

- » पुलिस ने नेताओं को लिया हिरासत में, विपक्ष बोला-भाजपा हारती है तो पुलिस को आगे करती है
 - » राहुल-अखिलेश ने संभाला मोर्चा, विपक्ष के सभी बड़े नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें
 - » संसद मार्ग पर निर्वाचन सदन तक विपक्ष का काफिला निकला
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क



यह राजनीतिक नहीं संविधान बचाने की लड़ाई है : राहुल

दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो (सरकार) बात नहीं कर सकते हैं। सच्चाई देश के सामने है। यह राजनीतिक नहीं संविधान की लड़ाई है। हमें साफ वोट लिस्ट चाहिए।

अखिलेश यादव ने की पुलिस कार्रवाई की आलोचना

समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव भी बैरिकेड पार कर दूसरी ओर धरने में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल हमें रोकने के लिए किया जा रहा है। यह टिप्पणी उन्होंने तब की जब पुलिस विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग तक मार्च करने से रोक रही थी और वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठ गए थे।



विरोध प्रदर्शन में 300 सांसद शामिल

इस मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, झीएमके सहित कई दलों के लगभग 300 सांसद भाग ले रहे हैं। दोनों सदनों के सांसदों ने तख्तीया उठाई है, जिन पर एसआई लोकतंत्र पर हमला है और वोट चोरी के नारे लिखे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे हैं और विपक्ष के सभी बड़े नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।

नई दिल्ली। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल है। एकजुट विपक्ष ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। विपक्ष को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया था। विरोध स्वरूप सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ गए।

इस बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। इन सब मामले को लेकर सियासी संग्राम भी मच गया। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में हल्ला बोल दिया है। वहीं इसको लेकर भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंक रही है। जब पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोका तो उसके बाद वे वहीं बैठकर धरना देने लगे।



सरकार कायर है : प्रियंका

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा, डरे हुए हैं, सरकार कायर है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने नारे लगाए। झंडिया ब्लॉक के नेता चुनावी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे हैं।

राहुल-प्रियंका हिरासत में

संसद से चुनाव आयोग तक मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी दीपक पुरोहित के अनुसार, विपक्ष के जिन भी नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। कितने सांसदों हिरासत में हैं? इसकी गिनती जारी है। यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। दिल्ली में रूट मार्च की परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धरने के लिए जंतर-मंतर जाने का सुझाव दिया है।

घबराया हुआ है चुनाव आयोग : प्रियंका चतुर्वेदी



शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जिस तरह से चुनाव आयोग घबराया हुआ है, वो चुने हुए जन प्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हमने तथ्यों के साथ बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हमने देशहित में बात रखी है और उनकी जवाबदेही बनती है लेकिन वो जवाब देने से बच रहे हैं।

घुसपैटियों को मतदाता बनाकर वो राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं : धर्मेंद्र प्रधान

विपक्ष के चुनाव आयोग मार्च पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं। इन दिनों देश देख रहा है कि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी काम अगर कोई कर रहा है, तो उसके सरगना भी राहुल गांधी ही हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी

है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर राज्य में, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है कि मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए वो लगातार काम करता है।



कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम पर झूठ बोलती है, कभी मलाराष्ट्र की उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, वो हर रोज झूठ का एक नया पहाड़ बनाते हैं। 2014, 2019 और 2024 में और उनके बीच अनेक राज्यों में निरंतर परराज्य के कारण कांग्रेस पार्टी एक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुकी है। पिछले 2-3 दिनों में वो जादू-विवाद हुआ, उसपर भारतीय नीडिया ने तथ्यों की जांच करके राहुल गांधी के हर एक झूठ का प्रमाण के आधार पर बेनकाब किया है।

यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है : खरगे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खरगे ने कहा, अगर कोई सरकार चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचने नहीं देती तो उस सरकार को क्या डर है, यह हमें नहीं पता, यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने विपक्ष के पैदल मार्च कहा, हम केवल यह सवाल पूछ रहे हैं कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों के नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ गए हैं। ये लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। हमारे वोटों की चोरी हो रही है।



योगी ने भी यूपी में लूटा है वोट : अखिलेश यादव

» बिहार के बाद डबल आईडी विवाद यूपी पहुंचा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। डबल आईडी विवाद अब यूपी की राजनीति को भी प्रभावित करन लगा है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार किया है। सपा मुखिया ने यूपी में वोट लूट और बूथ लूट के गंभीर आरोप लगाए मीरापुर और अयोध्या की घटनाओं का जिक्र कर अखिलेश ने चुनाव आयोग की नींद तोड़ने की बात कही है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर दो वोटर आईडी रखने के आरोप के बाद, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। अखिलेश ने योगी पर वोट लूट और बूथ लूट में मदद करने का आरोप लगाया। इस विवाद को उत्तर प्रदेश से जोड़ते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बिहार के उपमुख्यमंत्री के



पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में बड़ी तादाद में आई महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व पर सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे।

पास दो वोटर आईडी हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वोट लूट में मदद कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी

गई। इसके अलावा, उन्होंने मीरापुर में कमिश्नर, एसएसपी और डीएम पर यह सुनिश्चित करने के लिए बल का उपयोग करने का आरोप लगाया कि लोग वोट डालने के लिए बाहर न निकलें।

पुरानी वीडियो दिखाकर भाजपा सरकार को घेरा

एक वीडियो में, अखिलेश यादव ने मीरापुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा महिला मतदाताओं पर बंदूक तानने की कथित घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने पूछा, क्या हमने महिलाओं पर

रिवॉल्वर तानने नहीं देखा? क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उन्होंने आगे कहा कि जब अधिकारी ही वोट लूटने के लिए अपराधी बन जाएं, तो कार्रवाई कौन करेगा?

तेजस्वी यादव ने भी लगाए आरोप

यह विवाद तब शुरू हुआ जब राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के दो वोटर आईडी नंबर हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए सिन्हा ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

वोट चोरी पर सपा प्रमुख ने मिलाए राहुल गांधी के सुर में सुर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। उस पर वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं, उसकी सफाई देना स्वयं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एवं चुनावी पारदर्शिता के लिए जरूरी है। जनता का विश्वास किसी संवैधानिक संस्था से ढिगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा भ्रष्टाचार

का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय। अखिलेश ने रविवार को जारी अपने बयान में कहा कि सबसे ज्यादा फर्जी वोटर भाजपा ने बनवाए हैं। भाजपा के चुनावी हथकंडे अब उजागर हो चुके हैं। भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से अपने समर्थक फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है और चुनावी अधिकारियों से साठगांठ कर कभी अपने विरोधियों के नाम मतदाता सूची से गायब कर देती है।

सरकारी दस्तावेजों को गायब कर रही भाजपा : भारद्वाज

» दिल्ली में जलभराव पर सियासी सवाल , आप ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश देखने को मिली। जिसके चलते की इलाकों में भारी जलभराव हुआ। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार नालों के डिसिल्टिंग (गाद निकालने) से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज को नष्ट कर रही है।

डिसिल्टिंग में भाजपा सरकार और उनके अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, रक्षाबंधन पर भी लोगों को जलभराव का शिकार होना पड़ा, कई लोगों की जलभराव की वजह से मौत हुई है। ढाई साल के बच्चे की खुले हुए सीवर में डूबने से मौत हो गई।

डिसिल्टिंग कराने में भाजपा सरकार और उनके अधिकारियों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इनके अधिकारियों ने पिछले साल



थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट दिखाए सरकार

उन्होंने कहा, मैंने आर्टीई लगाकर पूछा कि मुख्य सचिव को जो नौले पत्र लिखकर डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, उसका क्या हुआ? मेरी आर्टीई के जवाब में मुख्य सचिव के ऑफिस ने बताया कि हमें ऐसा कोई पत्र मिला ही नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली की भाजपा सरकार आधिकारिक दस्तावेजों को गायब कर रही है।

भी डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई और ना इस साल कराई है। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है अब दिल्ली सरकार नालों के डिसिल्टिंग से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज को नष्ट कर रही है।

आनंद शर्मा का कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, वे अभी भी कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हैं। शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संबोधित अपने त्यागपत्र में कहा कि जैसा कि मैंने पहले कांग्रेस कार्यसमिति और कांग्रेस कार्यसमिति अध्यक्ष, दोनों को सूचित किया है, मेरे विचार से, क्षमतावान और प्रतिभाशाली युवा नेताओं को शामिल करने के लिए समिति का पुनर्गठन आवश्यक है। इससे इसके कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित होगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मैं विदेश मामलों के विभाग (डीएफए) के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ ताकि इसका पुनर्गठन हो सके। यह इस्तीफा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कई देशों की यात्रा के कुछ दिनों बाद आया है। आनंद शर्मा, एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में शामिल थे।

एक हफ्ते में यूपी में नहीं खुले स्कूल तो देंगे धरना : संजय

» आप सांसद ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर में जयसिंहपुर के सराय नौरंग प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्कूली बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हमारा स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो के नारे लगाए। रक्षाबंधन पर बच्चों ने सांसद को राखी बांधी। उनसे विद्यालय पुनः शुरू करवाने में मदद मांगी।

बच्चों की मांग पर सांसद ने आश्वासन दिया कि यदि एक हफ्ते के भीतर स्कूल शुरू नहीं हुआ तो वह धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के अनुसार किसी भी बच्चे का सरकारी स्कूल एक किमी से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन, सराय नौरंग के बच्चों को एक किमी दूर और हाईवे पार करके पढ़ने जाना पड़ रहा है। योगी सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार आने वाली पीढ़ी को अनपढ़ रखना चाहती है। संजय सिंह ने आगे कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। कई केंद्रीय मंत्रियों के घर 30-35 वोट दर्ज थे। छोटे प्लैट्स में 22-



प्रभु श्रीराम के नाम पर जनता को लूट रही भाजपा

अयोध्या में 150 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज की सड़क धसने पर सांसद ने सरकार को घेरा। कहा कि सरकार प्रभु श्रीराम के नाम पर जनता को लूट रही है।

25 वोट बनाए गए थे। बुरारी निवासी व्यक्ति का वोट केंद्रीय मंत्री के घर बना था। दिल्ली चुनाव में इसका खुलासा भी किया गया था। उन्होंने दावा किया कि एक ही मतदाता कई राज्यों में वोट डाल रहा है। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है।



वामुलाहिजा

काहूत : हसन अली

अपना वादा पूरा करें पीएम : सुरिंदर चौधरी

» बोले जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम- इस बार लाल किले से पूर्ण राज्य का किया जाए ऐलान

4पीएम न्यूज नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने उम्मीद जताई कि इस बार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ऐलान कर दें कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस किया जाता है। ताली मोड़ बारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुरिंदर चौधरी ने 5 अगस्त 2019 की घटनाओं को याद किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से एक पूर्ण राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को यह फैसला कभी मंजूर नहीं था। ऐसे में डिप्टी



केंद्र ने यह वादा किया था कि सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यह सबसे सही समय है। उम्मीद है कि पीएम मोदी लाल किले से अपने भाषण में इसका ऐलान करेंगे। सुरिंदर चौधरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को बसों में फ्री सफर मिल रहा है। शादी के लिए सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। 200 यूनिट फ्री बिजली, सीनियर सिटिजन, विधवा और दिव्यांगजन को पेंशन आदि कई योजनाएं सरकार चला रही है।

R3M EVENTS
ACTIVATION · EVENTS · EXHIBITION

R3M EVENTS
4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@r3mevents.com, Mob : 095406 11100

बांग्लादेशी या बहाना? सिर्फ मुसलमान थे निशाना

गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई के बाद हजारों लोग बेघर

» गुजरात में बेघर हजारों मुसलमान!

» मोदी मॉडल पर उठे सवाल पीड़ितों को कब मिलेगा इंसाफ?

» सरकार नहीं ले रही सुध

4पीएम न्यूज नेटवर्क

अहमदाबाद। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार ने इसे पाकिस्तान से जुड़ा माना और सख्त कदम उठाए लेकिन इस घटना का असर सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भी दिखा। पहलगाम हमले के ठीक एक हफ्ते बाद 28 अप्रैल को अहमदाबाद पुलिस ने चंदोला झील के पास की झुग्गी बस्तियों में छापेमारी शुरू की। पुलिस का कहना था कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं। इस अभियान में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। मई 2025 तक चंदोला झील के आसपास की झुग्गी बस्तियों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लगभग 12,500 गरीब परिवारों के घर और दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गईं, इनमें ज्यादातर मुस्लिम परिवार थे।

इस कार्रवाई में लोगों को न तो पहले से कोई नोटिस दिया गया न ही उन्हें अपना सामान बचाने का मौका मिला और न ही उनके लिए कोई पुनर्वास योजना बनाई गई। यह सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का उल्लंघन था जो कहते हैं कि बस्तियों को तोड़ने से पहले लोगों को उचित नोटिस और पुनर्वास का इंतजाम करना जरूरी है। इसके बाद हजारों लोग बेघर हो गए। कुछ लोग तिरपालों के नीचे रहने को मजबूर हैं, कुछ सरकारी आश्रय गृहों में गए और कुछ रिश्तेदारों के पास चले गए। भारी बारिश में कई परिवार ऑटोरिक्षा में रातें बिता रहे हैं। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है और परिवारों को गुजारा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अहमदाबाद में चंदोला झील के आसपास की बस्तियाँ दशकों से मजदूरों, छोटे दुकानदारों और मेहनतकश परिवारों का घर थीं। यहां ज्यादातर लोग मजदूरी, छोटे-मोटे काम, या ऑटोरिक्षा चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। इन बस्तियों में मुस्लिम परिवारों की संख्या ज्यादा थी लेकिन हिंदू और अन्य समुदाय के लोग भी रहते थे। लोग यहां मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने और बेहतर जिंदगी देने की कोशिश में थे। इन झुगियों में छोटे-छोटे घर थे। जिनमें परिवार अपने सीमित साधनों में खुश रहते थे। बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ने जाते थे और महिलाएं घर चलाने के साथ-साथ छोटे-मोटे काम करती थीं। यह बस्ती भले ही गरीब थी, लेकिन यहाँ एक समुदाय था। जहां लोग एक-दूसरे की मदद करते थे। दुकानें, छोटे-मोटे कारोबार और मेहनत की जिंदगी इस बस्ती की पहचान थी। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने पूरे देश में सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी शुरू की। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि चंदोला झील की बस्तियों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए



बुलडोजरों ने लगभग 12,500 घरों और दुकानों को तहस-नहस कर दिया

आपको बता दें कि 28 और 29 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ यह अभियान मई तक चला। 20 मई 2025 को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चंदोला झील के पास की बस्तियों को पूरी तरह से तोड़ दिया। बुलडोजरों ने लगभग 12,500 घरों और दुकानों को तहस-नहस कर दिया।

बता दें इस कार्रवाई में लोगों को पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई कि उनके घर तोड़े जाएंगे। कई लोग रात को सो रहे थे, जब बुलडोजर आए। परिवारों को अपना सामान, जैसे कपड़े, बर्तन, या जरूरी दस्तावेज निकालने का समय नहीं दिया गया। कई लोगों के कीमती सामान, पैसे

और दस्तावेज मलबे में दब गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर किसी बस्ती को तोड़ा जाता है, तो वहां रहने वालों को दूसरी जगह बसाने का इंतजाम करना जरूरी है लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग बेघर हो गए और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया।

लोग डर, चिंता, और अनिश्चितता में जी रहे

वहीं कई बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। कुछ परिवारों के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो कुछ के पास बच्चों को स्कूल भेजने का समय और साधन नहीं है। कई बच्चे अब मजदूरी करने लगे हैं। परिवारों को गुजारा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। ये कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर मिलता है, जिससे लोग और गरीबी में डूब रहे हैं। घर टूटने और बेघर होने का बच्चों और बड़ों पर गहरा मानसिक असर पड़ा है। लोग डर, चिंता, और अनिश्चितता में जी रहे हैं।

कई परिवार लकड़ी के डंडों और तिरपालों से बने घरों में रहने को मजबूर

बता दें कि इस कार्रवाई में हजारों लोग बेघर हो गए। कुछ लोग तिरपालों के नीचे रहने लगे, कुछ सरकारी आश्रय गृहों में गए और कुछ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए लेकिन ज्यादातर लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था। बस्ती टूटने के बाद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कई परिवार लकड़ी के डंडों और तिरपालों से बने अस्थायी घरों में रह रहे हैं। ये घर बारिश, गर्मी, या ठंड से कोई सुरक्षा नहीं देते। बच्चे और बूढ़े लोग बीमार पड़ रहे हैं।



वहीं जब भारी बारिश होती है, तो कुछ लोग ऑटोरिक्षा में रात बिताते हैं। ये

ऑटोरिक्षा पास के इलाकों में रहने वाले झड़वरों के हैं जो इन परिवारों को थोड़ी

जगह दे देते हैं लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं है। कुछ लोग सरकारी आश्रय गृहों में गए लेकिन वहां जगह कम है और हालात अच्छे नहीं हैं। खाना, पानी, और साफ-सफाई की कमी के कारण लोग परेशान हैं। जिनके पास रिश्तेदार थे, वे शहर या बाहर उनके घरों में चले गए लेकिन वहां भी जगह और संसाधनों की कमी के कारण मुश्किलें हैं। कई पुरुष हिरासत से बचने के लिए बस्ती छोड़कर भाग गए। इससे परिवारों की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों पर आ गई।

रह रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। वहीं इस दावे के आधार पर 28 अप्रैल को पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। पुलिस ने रात के समय बस्तियों में घुसकर लोगों को उनके घरों से निकाला। कई लोग उस समय सिर्फ रात के कपड़ों में थे। पुरुषों, महिलाओं, और यहां तक कि बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि वे उन लोगों की जांच कर रहे हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं लेकिन इस अभियान में कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज थे। कुछ लोगों का कहना था कि वे महाराष्ट्र, बिहार, या अन्य राज्यों से आए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी मानकर हिरासत में ले लिया।

यह कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थी : गुजरात पुलिस

गुजरात पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांधवी ने कहा कि हमने 1,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। कुछ लोग अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि चंदोला झील की बस्तियों में कई लोग बिना दस्तावेज के रह रहे थे लेकिन कई लोगों ने दिखाया कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज थे। फिर भी, उन्हें हिरासत में लिया गया या उनके घर तोड़ दिए गए।

कुछ नेताओं ने इसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई बताया

वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह अभियान सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए नहीं था बल्कि इसमें खास समुदाय को निशाना बनाया गया। कुछ नेताओं ने इसे मुस्लिम-विरोधी कार्रवाई बताया। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसी कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि बिना सबूत के लोगों को बेघर करना और उनकी जिंदगी बर्बाद करना गलत है। चंदोला झील की बस्ती को तोड़ने की कार्रवाई ने हजारों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। ये

लोग पहले से ही गरीबी में जी रहे थे और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, परिवार कर्ज में डूब रहे हैं और लोग तिरपालों और ऑटोरिक्षा में रातें बिता रहे हैं। यह सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत का सवाल है। बता दें कि सरकार को सुरक्षा के साथ-साथ लोगों के हक की भी चिंता करनी चाहिए। बिना नोटिस और पुनर्वास के बस्तियाँ तोड़ना न सिर्फ गलत है बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। इन परिवारों को न्याय और सहायता की जरूरत है ताकि वे फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

रोजगार का स्वरूप बदलती 'तकनीक'

66

शिक्षा प्रणाली को भी समय के साथ अपडेट किया जाए, ताकि भविष्य के श्रमिक बदलती तकनीकी मांगों के लिए तैयार हों। इसके अलावा, छंटनी के दौरान एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल (सोशल सिव्योरिटी नेट) और बेरोजगारी भत्ता जैसी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, जिससे प्रभावित लोग नई नौकरी तलाशने के दौरान आर्थिक संकट से बच सकें।

तकनीकी क्रांति ने दुनिया को जिस तेजी से बदला है, वह अभूतपूर्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक ओर तकनीक ने उत्पादन क्षमता, दक्षता और सुविधा में बढ़ोतरी की है, वहीं दूसरी ओर इसने रोजगार के पारंपरिक स्वरूप को चुनौती भी दी है। आज एक मशीन या एल्गोरिदम वह काम कुछ सेकंड में कर देता है, जिसे पहले दर्जनों लोग घंटों में पूरा करते थे। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी कंपनियों ने लागत कम करने और 'प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने' के नाम पर भारी पैमाने पर छंटनी की है। तकनीक का प्रभाव केवल निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहां तक कि रचनात्मक क्षेत्रों में भी एआई और ऑटोमेशन का प्रवेश हो चुका है।

जहां एक बैंक का काउंटर कर्मचारी कभी सैकड़ों ग्राहकों से रोजाना मिलता था, अब वही काम एक मोबाइल ऐप कर रहा है। कॉल सेंटर में, चैटबॉट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। फैक्ट्री में, मशीनें बिना थके 24 घंटे उत्पादन कर रही हैं। इन बदलावों ने कंपनियों के लिए मुनाफा और तेज़ डिलीवरी सुनिश्चित की है, लेकिन इंसानी श्रमिकों के लिए यह बदलाव नौकरी खोने के खतरे के रूप में सामने आया है। छंटनी का असर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी होता है। नौकरी जाने के बाद व्यक्ति की आय घट जाती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और परिवार की स्थिरता पर भी असर पड़ता है। लंबे समय तक बेरोजगारी रहने से कौशल पुराना हो सकता है, जिससे दोबारा नौकरी पाने की संभावना घटती है। खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी शिक्षा या प्रशिक्षण पारंपरिक कार्यप्रणालियों पर आधारित है, यह तकनीकी बदलाव और भी मुश्किल साबित होता है। हालांकि, यह भी सच है कि तकनीक पूरी तरह से रोजगार समाप्त नहीं करती, बल्कि उसके स्वरूप को बदल देती है। नई तकनीकों के साथ नए प्रकार की नौकरियां भी पैदा होती हैं – जैसे डेटा विश्लेषक, एआई ट्रेनर, साइबर सिव्योरिटी विशेषज्ञ, और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। लेकिन समस्या यह है कि इन नौकरियों के लिए जो कौशल चाहिए, वे हर उस व्यक्ति के पास नहीं होते जिसकी नौकरी छिनी है। नतीजतन, तकनीकी बदलाव और कौशल विकास के बीच का अंतराल एक गंभीर चुनौती बन जाता है। सरकारों और कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे इस अंतराल को कम करें। कर्मचारियों के कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) और पुनः प्रशिक्षण (री-स्किलिंग) के लिए निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

सामंजस्य से तय हो जनता के प्रति जवाबदेही

डॉ. जगदीप सिंह

भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपनी संसद के माध्यम से जनता की आवाज को प्रतिनिधित्व देता है। लोकसभा और राज्यसभा, जो भारत की द्विसदनीय संसद के दो अंग हैं, राष्ट्रीय नीतियों, कानून निर्माण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में संसद के सत्रों में विपक्ष के हंगामे और व्यवधानों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है। इन व्यवधानों का न केवल संसदीय कार्यवाही बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी दलों द्वारा संसद में हंगामा करना कोई नई बात नहीं है। यह अक्सर सरकार की नीतियों, विधेयकों या किसी विवादास्पद मुद्दे पर असहमति जताने का एक तरीका होता है।

उदाहरण के लिए, 2021 के मॉनसून सत्र में इंश्योरेंस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी, कागज फाड़ने और काले झंडे दिखाने जैसे कदम उठाए थे। हाल ही में, 2025 के मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई। ये व्यवधान न केवल समय की ही बर्बादी करते हैं, बल्कि संसद की गरिमा और कार्यकुशलता को भी प्रभावित करते हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा सभापति के आसन के समीप नारेबाजी, तख्तियां लहराना और कार्यवाही में बाधा डालना आम बात हो गई है। 2023 के शीतकालीन सत्र में, सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण 146 सांसदों को निर्लंबित किया गया, जो संसद के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम था। संसद की कार्यवाही में व्यवधान का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय नुकसान के रूप में सामने आता है। संसद को चलाने की लागत बहुत अधिक है, जिसमें

सांसदों के वेतन, भत्ते, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों का खर्च और अन्य प्रशासनिक लागत शामिल हैं।

एक अनुमान के अनुसार, संसद को चलाने की प्रति मिनट लागत लगभग 2.5 लाख रुपये है, जो प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपये के बराबर है। वर्ष 2025 के मॉनसून सत्र में, राज्यसभा के उपसभापति के अनुसार, विपक्ष के हंगामे के कारण 51.3 घंटे की कार्यवाही बर्बाद हुई, जिसका अनुमानित वित्तीय नुकसान 76 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि करदाताओं से आती है, और इसका दुरुपयोग न केवल आर्थिक नुकसान है,



बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही की कमी को भी दर्शाता है। वित्तीय नुकसान के अलावा, संसद में हंगामे का सबसे गंभीर प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है। संसद का प्राथमिक उद्देश्य जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना और कानून बनाना है। व्यवधानों के कारण महत्वपूर्ण विधेयक, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक या इनकम टैक्स बिल, बिना उचित चर्चा के स्थगित हो जाते हैं या जल्दबाजी में पारित कर दिए जाते हैं। इससे न केवल नीतियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि जनता के हितों की भी उपेक्षा होती है। हंगामे के कारण संसद में बहस की गुणवत्ता में भी कमी आई है। सांसदों का ध्यान विधायी चर्चा के बजाय मीडिया में सुर्खियां बटोरने और टकराव पर केंद्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, नागरिकों की प्रमुख चिंताएं, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, संसद में प्रभावी ढंग से उठाई नहीं जातीं। यह स्थिति संसद के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर

करती है और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। संसद को देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है, लेकिन बार-बार होने वाले हंगामे और सांसदों का अमर्यादित व्यवहार इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जनता चाहती है कि संसद पूरे समय चले, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच सहमति बने। हालांकि, विपक्ष का यह तर्क कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती है, और सत्तापक्ष का यह आरोप कि विपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी को उजागर करता है।

संसद में व्यवधानों को कम करने और इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर संवाद और सहमति बनाने की जरूरत है। कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठकों में सभी पक्षों को शामिल कर मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा तय किया जा सकता है।

21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए संसद की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी सुधारों से कार्यवाही को सुचारू बनाया जा सकता है सांसदों को जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए और राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। राजनीतिक टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। सांसदों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम और अनुशासनात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए। साथ ही, हंगामे के लिए जिम्मेदार सांसदों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

दिनेश सी शर्मा

देश में चल रहे मानसून मौसम में पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जैसा कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान दिया था। कई राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के कारण आपदाएं जैसे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं। हिमालयी क्षेत्र-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में लगातार, व्यापक और तीव्र बारिश हुई है। इस मौसम की सबसे भयंकर आपदाओं में से एक उत्तरकाशी जिले के धराली में आई, जहां कथित रूप से बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने जान-माल का नुकसान किया। यह क्षेत्र की पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील स्थिति में अनियंत्रित विकास के खतरे की गंभीर याद दिलाता है। मैदानों में भी मानसून का कहर जारी है, जहां बड़े शहरों में सड़कों पर जलभराव, जान-माल के नुकसान और पुरानी संरचनाओं का ढह जाना देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर जलजमाव के कारण भारी ट्रैफिक जाम, सड़कों और राजमार्गों पर कार और ट्रकों का सिंक होल में गिरना, स्कूलों और कार्यालयों में फंसे लोग तथा बिजली की चपेट में आने जैसी दुखद घटनाओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुछ नए बने हवाई अड्डों की इमारतें लगातार बारिश को सहन नहीं कर पाईं। प्रभावित शहर जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र और आउटसोर्सिंग हब हैं। बारिश से होने वाले प्रभावों को केवल 'प्रकृति का क्रोध' मान लेना गलत होगा। जो कुछ भारतीय शहर मानसून में जलभराव बढ़ने की जिस चुनौती को झेल रहे हैं, वह अताकिक शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे की अनदेखी, नगर निगम के नियमों के उल्लंघन, हरियाली और खुले क्षेत्रों के कटाव, बड़े पैमाने पर कंक्रीट का उपयोग आदि

शहरीकरण व जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझें



का संयुक्त परिणाम है। इसके ऊपर जलवायु परिवर्तन भी है, जो स्वयं मानव निर्मित समस्या है। दशकों से वैज्ञानिक अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि की चेतावनी दे रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है।

एक चरम मौसम घटना तब होती है जब किसी स्थान पर सामान्य मात्रा से कहीं अधिक वर्षा या हिमपात होता है, जैसा कि हमारे कई शहरों में हो रहा है। किसी शहर या क्षेत्र की औसत वर्षा सामान्य सीमा में रह सकती है, लेकिन कुछ दिनों या स्थानों पर बहुत कम समय में भारी वर्षा होती है, जिससे जलजमाव और स्थानीय बाढ़ होती है। यह स्थिति केवल बिगड़ती ही जाएगी क्योंकि भारत में तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है। वर्तमान अनुमान के अनुसार, 2050 तक लगभग एक अरब भारतीय शहरों में रह रहे होंगे। लेकिन अगर भारतीय शहर अपनी वर्तमान विकास दिशा पर चलते रहे, तो वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे, जैसा कि विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत के शहर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और बड़ी संपत्ति के केंद्र होने के कारण जलवायु प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील

हैं। शहरों में ग्रामीण इलाकों की तुलना में जलवायु प्रभाव और आपदाएं अधिक होती हैं क्योंकि वे अत्यधिक आपस में जुड़ी हुई प्रणालियों पर निर्भर हैं। जब मुख्य बुनियादी ढांचा जैसे राजमार्ग या बिजली ग्रिड टूटते हैं, तो यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देता है जिससे बुनियादी ढांचे की विफलता होती है और शहर ठप हो जाता है।

बाढ़ सड़कें बंद कर व यातायात बाधित कर सकती है, बिजली लाइनों को प्रभावित और आर्थिक नुकसान कर सकती है, जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है। हर साल मानसून के कारण हो रही इस अराजकता को देखते हुए स्पष्ट है कि हमारे शहर आगे के शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। शहरों के पास इन प्रभावों को प्रबंधित करने की सीमित क्षमता है। उनका नियोजन और प्रबंधन प्रणाली तेजी से हो रहे शहरीकरण, जलवायु प्रभावों और विकास तथा सेवाओं की मांग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। मौजूदा प्रणाली पुरानी हो चुकी है-कई मामलों में, ये ब्रिटिश राज काल से विरासत में मिली हैं। उदाहरण के लिए, हैदराबाद की नालियां और वर्षाजल निकासी प्रणाली

सदी पहले सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लगभग पांच लाख की आबादी के लिए डिज़ाइन की गई थी। उस समय यह प्रणाली आधुनिक मानी जाती थी और भविष्य के विकास तथा सौंदर्यशास्त्र व शहरी नियोजन जैसी चिंताओं को ध्यान में रखती थी। हैदराबाद को झीलों और बागों का शहर माना जाता था, जहां प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। यह सब तेजी से बढ़ते भौतिक संरचना और जनसंख्या की उच्च घनत्व के कारण नष्ट हो गया। परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। यह कहानी लगभग हर बड़े भारतीय शहर की है। कई शहर तटीय क्षेत्रों या बड़े और छोटे नदियों के बाढ़ से बने मैदानों के किनारे स्थित हैं।

शहरीकरण से सतह जल अवशोषण कम हो जाता है, जिससे पहले कम जोखिम वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। शहर लगातार बाढ़ मैदानों पर कब्जा कर रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1985 से 2015 के बीच, बाढ़-रहित क्षेत्रों में बसाव क्षेत्र 82 प्रतिशत और उच्च बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में 102 प्रतिशत बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के संयुक्त प्रभाव से वर्षाजल संबंधी या सतही जल बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ने की संभावना है। निःसंदेह, इस समस्या का समाधान शहरों को जलवायु-लचीला बनाकर तैयार करना है। इसके लिए हमें शहर-विशिष्ट जलवायु कार्ययोजनाएं बनानी होंगी। वर्तमान में ये प्रयास न के बराबर हैं। सभी राज्यों के पास सामान्य कार्ययोजनाएं हैं, जिनका अधिकांशतः क्रियान्वयन कमजोर है या वे केवल कागजों तक सीमित हैं। शहरी क्षेत्रों की चुनौतियां विविध हैं, जिनके लिए समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। स्थानीय जोखिम इतिहास के आधार पर शहरी बाढ़ से निपटने के लिए विशिष्ट रणनीतियां बनानी होंगी।

1315 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में शुमार है और एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस पुल के बनने के बाद जम्मू तवी से कटरा होते हुए श्रीनगर तक रेल मार्ग के जरिए पहुंचना काफी सरल हो जाएगा और यात्रा में वक्त भी कम लगेगा। अभी तक भारतीय रेलवे केन्द्र शासित प्रदेश के जम्मू तक ही सीमित था। ट्रेन का टिकट बुक करने पर जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन राजधानी श्रीनगर तक नहीं, बल्कि जम्मू तवी तक ही जाती थीं। इसके आगे का रास्ता लोगों को सड़क मार्ग के जरिए श्रीनगर (कश्मीर घाटी) तक तय करना होता था। जम्मू तवी से श्रीनगर की दूरी लगभग 350 किमी दूर है। जिसका सफर तय करने में लगभग छह घंटे लग जाते हैं। हालांकि ठंड के मौसम में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद होने का खतरा रहता है, जिससे कश्मीर तक जाने के लिए मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाता है या फिर भारत के किसी भी शहर से हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब जम्मू तवी से श्रीनगर तक रेल मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। अगर आप वैष्णो देवी धाम गए हैं तो कटरा से कश्मीर की रेल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा चिनाब रेलवे ब्रिज के पास कई और खूबसूरत स्थल हैं, जहां का नजारा आप ट्रेन के यात्रा के दौरान तो देख ही सकते हैं। साथ ही अगर आप इन्हें करीब से देखना चाहते हैं तो वहां तक पहुंच भी सकते हैं।

चिनाब ब्रिज

के पास ये जगहें किसी जन्म से कम नहीं

कटरा

चिनाब रेलवे ब्रिज की यात्रा श्री वैष्णो देवी धाम कटरा रेलवे स्टेशन से ही शुरू होती है। चिनाब ब्रिज कटरा से 40 किमी दूर है। यह शहर वैष्णो देवी धाम के लिए प्रसिद्ध है और पहाड़ों की बीच बसा है। यात्रा के बाद यहां की वादियां और स्थानीय बाजारों को घूमने जा सकते हैं। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने के साथ ही आप शिवखोरी गुफा मंदिर भी जा सकते हैं। यह एक प्राकृतिक गुफा है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहां ट्रेकिंग और अध्यात्म दोनों का अनुभव मिलता है।

पटनीटॉप

कश्मीर के उधमपुर जिले में पटनीटॉप स्थित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहां घने जंगलों, पहाड़ों और दूर तक फैले हरे-भरे घास के मैदानों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह जगह परफेक्ट है। आप स्कीइंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, जिप लाइनिंग और घुड़सवारी जैसी एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं।

डोडा जिला

जम्मू कश्मीर में एक बेहद शांत, खूबसूरत और सुकून भरा स्थान डोडा जिला है। यहां भाल पादरी का मनोरम दृश्य आपको बार-बार आने के लिए मजबूर कर देगा। माता चंडी मंदिर स्थित है और सूफी गांव को भी घूमने जा सकते हैं।



हंसना मना है

रिश्तेदार- बेटा आगे जिंदगी में क्या करोगे... लड़का - कुछ भी करूंगा लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा...

पिता (अपनी बेटे से) - बेटे, पहले तुम मुझे पापा बुलाती थी, अब डैड क्यों कहने लगी हो... बेटे - वो पापा बोलने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है ना...

क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा- बताओ, कांटों भरे रास्ते पर आपका साथ कौन देगा, पति, पत्नी, भाई, बहन, मां-बाप, प्रेमी, प्रेमिका या दोस्त... पप्पू खड़े होकर बोला - सर चप्पल... फिर मास्टर जी ने भी चप्पल से की पप्पू की पिटाई...

पति-मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता.. हकीम-माशाल्लाह ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है..

एक महिला एक साधु के पास गई और बोली-महाराज! आपने प्रवचन में कहा था, अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। पर जब मैं आईना देखती हूं, तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर हूं तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूं? साधु ने कहा-बेटे यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है और गलतफहमी कोई पाप नहीं।

कहानी

संन्यासी की जड़ी-बूटी

एक वृद्ध संन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जबसे युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी-बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है, कृपया आप मुझे वो जड़ी-बूटी दे दें। संन्यासी बोला, देवी मैं तुम्हें वह जड़ी-बूटी जरूर दे देता लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला बोली-आपको क्या चाहिए मुझे बताइए मैं लेकर आऊंगी, संन्यासी-मुझे बाघ की मूँछ का एक बाल चाहिए, अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी, बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा, बाघ उसे देखते ही दहाड़ा, महिला सहम गयी और तेजी से वापस चली गयी। महीना बीतते-बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गयी, और अब वह उसे देख कर सामान्य ही रहती है। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी, और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी और एक दिन उसने बाघ की मूँछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किये संन्यासी के पास पहुंची और बोली मैं बाल ले आई बाबा-बहुत अच्छे और ऐसा कहते हुए संन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया, अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किये और आपने इसे जला दिया अब मेरी जड़ी-बूटी कैसे बनेगी? महिला बोली- अब तुम्हें किसी जड़ी-बूटी की जरूरत नहीं है, संन्यासी बोला-जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया, जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अन्दर प्रेम भाव जागृत करो। महिला संन्यासी की बात समझ गयी, अब उसे उसकी जड़ी-बूटी मिल चुकी थी।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आनंद शर्मा

मेघ 	आज एकाएक पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लापरवाही न करें। दूर से दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यर्थ दौड़धूप होगी। काम में मन नहीं लगेगा।	तुला 	नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुख के साधन जुटेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यवसाय लाभदायक रहेगा।
वृषभ 	प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। लाभ देगा। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी।	वृश्चिक 	वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय सताएगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।
मिथुन 	आज अचानक धन की फिजूलखर्ची ज्यादा होगी। शत्रु भय रहेगा। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।	धनु 	स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। विवाद से वलेश हो सकता है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।
कर्क 	अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं।	मकर 	कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि अपमान हो।
सिंह 	कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आएगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। कुसंगति से बचें। किसी व्यक्ति के काम की जवाबदारी न लें। स्वयं के काम पर ध्यान दें।	कुम्भ 	नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं। सुख के साधन जुटेंगे। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। उत्साह बना रहेगा।
कन्या 	घर के छोटे सदस्यों संबंधी चिंता रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। जल्दबाजी न करें।	मीन 	कारोबारी यात्रा आज लाभदायक रहेगी। नौकरी कर रहे जातक कार्य में विवेक का प्रयोग करें। समस्याएं कम होंगी। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय रहेगा।



उदयपुर फाइल्स को लेकर बोलीं प्रीति झंगियानी, कहा- किसी को भी डरने की जरूरत नहीं

शुरू से विवादों में फंसी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज शुक्रवार 08 अगस्त को रिलीज हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने से किया इनकार दिया है। आखिर फिल्म अब दर्शकों तक पहुंच रही है। इस फिल्म में काम कर रही अदाकारा प्रीति झंगियानी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कई बाधाओं का सामना करने के बाद फिल्म उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर को

बॉलीवुड

गपशप



आखिरकार हरी झंडी मिली है। कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म से पहले कल गुरुवार रात मेकर्स ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। फिल्म उदयपुर फाइल्स में विजय राज, प्रीति झंगियानी, कमलेश सावंत और मुश्ताक खान जैसे सितारे हैं। बीती रात स्क्रीनिंग में शामिल हुई प्रीति

झंगियानी ने फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने मीडिया से कहा, यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। किसी को भी सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। इसमें इंसानी स्वभाव और हकीकत को दिखाया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। फिल्म देखें और फिर कोई राय बनाएं। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। साल 2022 में टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी। इसके बाद उनकी दुकान में उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है।

बॉलीवुड

मन की बात

अच्छा किरदार न मिलने की वजह से मैं फिल्मों से दूर हूं: आशीष विद्यार्थी

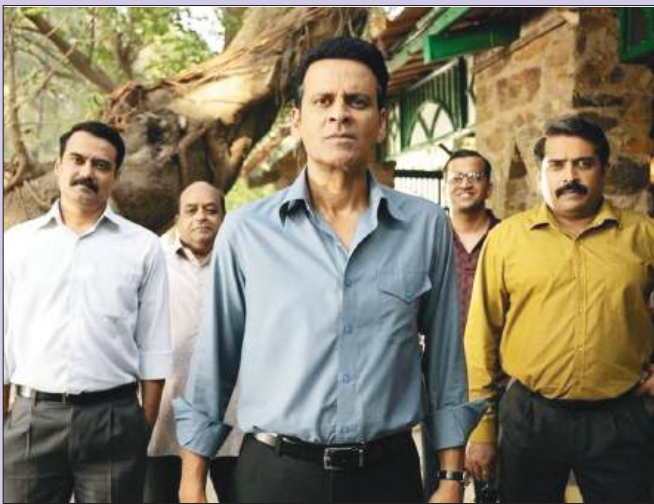


आशीष विद्यार्थी ने हाल ही में बताया है कि वह इन दिनों बड़े पर्दे पर क्यों नजर नहीं आते हैं। हाल ही में उनके कई फैंस ने उनसे यह सवाल पूछा था कि वह फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हैं। यूट्यूब पर अपने ब्लॉग में आशीष विद्यार्थी ने बताया है कि वह इसलिए फिल्मों में नहीं नजर आते हैं क्योंकि वह अच्छा किरदार चाहते हैं। आशीष विद्यार्थी ने 11 भाषाओं की लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। ऐसे में उनका कहना है मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूं। उन्होंने बताया है कि वह फिल्मों में ऐसी भूमिका चाहते हैं जो उनकी काबिलियत के साथ इंसाफ कर सके। अपने ब्लॉग में आशीष ने इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात की। उन्होंने निर्देशकों और निर्माताओं से कहा अगर आपने अब तक हमें वह भूमिकाएं नहीं दीं जिसका मैं हकदार था, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब भी इन भूमिकाओं को मुझे नहीं दे सकते। आशीष के मुताबिक वह फिल्मों में रोल और शोहरत के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वह फिल्मों में ऐसे किरदार को निभाने का इंतजार कर रहे हैं कि जिससे वह दोबारा मशहूर हो जाएं। उन्होंने कहा मैं घर पर अवसाद में नहीं बैठा हूं। उनके मुताबिक वह वर्षों से अपने आप पर काम कर रहे हैं और अपने काम को निखार रहे हैं। आपको बता दें कि आशीष विद्यार्थी इन दिनों यूट्यूब पर अपने ब्लॉग पर वीडियो डालते हैं। वह कहीं भी जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं और नई चीजों को देखते हैं। इन सबकी वीडियो वह अपने यूट्यूब ब्लॉग पर डालते हैं। आशीष विद्यार्थी को फिल्म किल से बहुत शोहरत मिली। वह हाल ही में सीरीज राणा नायडू में नजर आए थे।

अगले महीने ओटीटी पर आ रही मनोज बाजपेयी की फिल्म 'इंस्पेक्टर जेडे'

मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी मशहूर वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 को लेकर चर्चा में हैं। वह इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को उनकी एक नई फिल्म इंस्पेक्टर जेडे का पहला पोस्टर जारी किया गया है। फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ जिम सर्भ अहम किरदार में नजर आएंगे।

नेटपिलक्स ने गुरुवार को नई फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है चोर-पुलिस का खेल अब शुरू होगा। इंस्पेक्टर जेडे ड्यूटी पर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर जेडे में मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ हैं। यह 5 सितंबर को नेटपिलक्स पर रिलीज हो रही है। फिल्म का पोस्टर अखबार की तरह है। इसमें मनोज बाजपेयी और जिम



सर्भ का फोटो बना है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म की कहानी 70-80

के दशक की मुंबई की कहानी हो सकती है। पोस्टर में दिख रहे फिल्म के टाइटल

के नीचे लिखा है क्या इंस्पेक्टर स्विमसूट किलर को पकड़ पाएंगे? पोस्ट देखकर लगता है कि फिल्म की कहानी स्विमसूट किलर पर आधारित होगी। यह अपराधी तिहाड़ जेल से भाग गया था। इंस्पेक्टर जेडे एक पुलिस अधिकारी थे, जो उसे पकड़ना चाहते थे।

खबरों की मानें तो फिल्म में मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर का रोल निभाएंगे तो वहीं जिम सर्भ स्विमसूट किलर के तौर पर नजर आएंगे। इसमें भालचंद्र कदम, सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक और हरीश दुधाड़े होंगे। फिल्म के निर्माता ओम राउत हैं। उन्होंने कहा इंस्पेक्टर जेडे की कहानी देखने और जश्न मनाने लायक है। यह नेटपिलक्स ऑरिजनल फिल्म है। 5 सितंबर को फिल्म ओटीटी पर ही रिलीज होगी।

इंसान नहीं तोता है इस लड़की का भाई हर साल बांधती है सोने की राखी

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर की रहने वाली स्वपन रक्षाबंधन का त्योहार बेहद अनोखे तरीके से मनाती हैं। उनका रक्षाबंधन मनाने का अंदाज बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, जो उन्हें खास बनाता है। दरअसल, अंबिकापुर के जोड़ा पीपल के पास रहने वाली स्वपन का कोई सगा भाई नहीं है। बचपन से ही उन्हें जानवरों से बेहद लगाव था और वह चाहती थी कि उनका कोई भाई हो जो भाई का फर्ज निभाए। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान उनके पास एक तोता आया, जिसका नाम उन्होंने 'हीर' रखा। तब से रक्षाबंधन पर वह तोते हीर को सोने की राखी बांधती हैं। स्वपन ने बताया कि 12वीं पास करने के बाद पहले लॉकडाउन में तोता हीर उनके पास आया था। उससे पहले वह खरगोश (रैबिट) के साथ रक्षाबंधन मनाती थीं, लेकिन हीर के आने के बाद वह हर साल उसे अपना भाई मानकर सोने की राखी बांधती हैं। उनके अनुसार, इंसानों में उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार रिश्तों में धोखा मिला है। उनका कहना है, इंसानों को राखी बांधो, तो अंत में वे धोखा देकर चले जाते हैं, लेकिन जानवर कभी धोखा नहीं देते। स्वपन कहती हैं कि उनका हीर उनसे कभी कुछ नहीं मांगता, बस साथ और प्यार चाहता है। उनके पास और भी तोते हैं, जिन्हें वह हर साल राखी बांधती हैं। बचपन से ही जानवरों के बीच रहने के कारण इंसानों से दूरी और जानवरों से नजदीकी उनकी पहचान बन गई है। वह कहती हैं, इंसानों का प्यार अक्सर झूठा होता है, लेकिन जानवरों का साथ सच्चा और भरोसेमंद होता है। स्वपन बताती हैं कि हीर उनके साथ हर जगह रहता है। चाहे स्कूटी की सवारी हो या घर पर समय बिताना। इसके अलावा, उनके पास तीन और तोते हैं, जिन्हें वह राखी बांधती हैं। वह पिछले 5 साल से तोते के साथ रक्षाबंधन मना रही हैं। स्वपन की दुनिया बाकी लोगों से अलग है। वह मानती हैं कि जो भाई भाई का असली फर्ज निभाए वही सच्चा भाई है। उनके लिए तोता हीर ही भाई और परिवार दोनों हैं। स्वपन के लिए हीर का जन्मदिन, रक्षाबंधन और नवरात्रि जैसे मौके बेहद खास होते हैं। नवरात्रि में वह व्रत रखती हैं और सांड बार मंदिर तक पैदल जाती हैं। वह तोते हीर के नाम से भंडारा भी करती हैं। उनके लिए हीर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है।



अजब-गजब

800 साल से भी पुरानी है यह परंपरा

रक्षाबंधन पर यहां बहनें नहीं बांधतीं भाई को राखी

छतरपुर। रक्षाबंधन के पर्व में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। बहनें इस पर्व पर भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती हैं लेकिन बुंदेलखंड के महोबा और छतरपुर जिले में रक्षाबंधन का पर्व तय दिन नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहां एक ऐतिहासिक परंपरा के चलते यह त्योहार एक दिन बाद मनाया जाता है। साथ ही इस दिन महोबा में ऐतिहासिक मेले का भी आयोजन होता है। इस धरती के वीरों को याद करने के लिए भव्य शोभायात्रा भी निकाली जाती है।

उत्तर प्रदेश के महोबा और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अधिकांश इलाकों में सदियों से रक्षाबंधन का त्योहार एक दिन बाद मनाने की परंपरा है। इसके पीछे भाई-बहन के प्रेम और एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी है। पंडित रमाकांत दीक्षित बताते हैं कि महोबा का अपना गौरवशाली इतिहास है। यहां रक्षाबंधन एक दिन बाद मनाने की परंपरा 1182 ई. के चंदेल शासनकाल से चली आ रही है। साथ ही छतरपुर जिले के आधे हिस्से में भी रक्षाबंधन का त्योहार एक दिन बाद मनाने की परंपरा है। दरअसल उस समय दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला कर दिया था। उस समय



महोबा में चंदेल शासक परमाल का राज था। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन यहां राजा पृथ्वीराज चौहान और महोबा के शूरवीर आल्हा-ऊदल के बीच घनघोर युद्ध चल रहा था, जिस वजह से विजय के बाद दूसरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। तभी से यह परंपरा यहां चली आ रही है। महोबा में 832 ईसा पूर्व में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने 7 लाख सैनिकों के साथ महोबा के राजा परमाल पर आक्रमण कर पांच शतों रख युद्ध न करने

की बात कही थी लेकिन राजा परमाल ने पांचों शतों को दुकरा दिया था। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया था। राजा परमाल के वीर योद्धा आल्हा-ऊदल ने पूर्णिमा के दिन पृथ्वीराज चौहान को धूल चटा यहां से भगा दिया था। पूरे दिन लड़ाई चलने के कारण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जा सका था, इसलिए एक दिन बाद इस पर्व को मनाया गया था। तभी से महोबा में रक्षाबंधन का पर्व इसी परंपरा से मनाया जाता है।

धनखड़ का लापता होना चिंता की बात : राउत

» यूबीटी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी उठाये सवाल

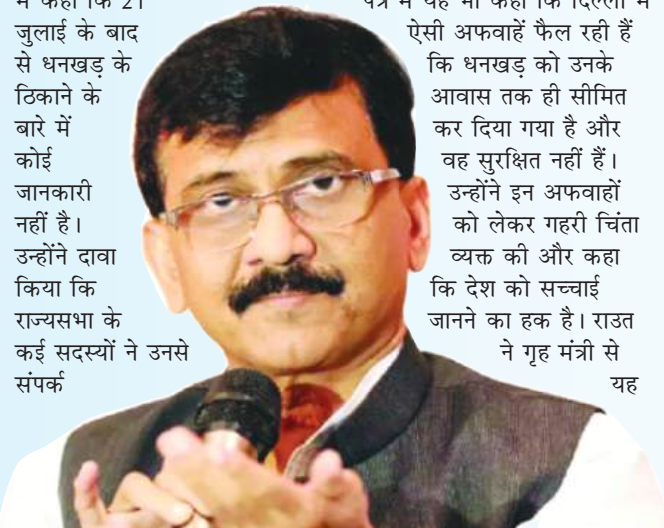
» देश को सच्चाई जानने का हक, सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे संजय राउत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल व शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के बाद उन्हीं की पार्टी के सांसद संजय राउत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लापता होने पर चिंता जताई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनका पता लगाने की मांग की है। राउत ने धनखड़ के ठिकाने को लेकर अफवाहों पर भी चिंता व्यक्त की है। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ठिकाने को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत

ने चिंता जताई है।

सोमवार को उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उनका पता लगाने की मांग की। संजय राउत ने अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा कि 21 जुलाई के बाद से धनखड़ के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा के कई सदस्यों ने उनसे संपर्क



करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। राउत ने कहा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति या उनके कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। राउत ने पत्र में यह भी कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि धनखड़ को उनके आवास तक ही सीमित कर दिया गया है और वह सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने इन अफवाहों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि देश को सच्चाई जानने का हक है। राउत ने गृह मंत्री से यह

गृहमंत्री इस मामले पर स्पष्टीकरण दें : सिब्बल

यह मामला तब और गंभीर हो गया जब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी धनखड़ के ठिकाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना है, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। उन्होंने भी गृह मंत्री से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।



सवाल भी किया, आखिर हमारे (पूर्व) उपराष्ट्रपति के साथ क्या हुआ? वह कहाँ हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? क्या वह सुरक्षित हैं? राउत ने आगे कहा कि अगर उन्हें सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करने पर विचार कर सकते हैं।

कांस्टीट्यूशन क्लब चुनाव को लेकर भाजपा में ही रार

» राजीव प्रताप और संजीव बलियान आमने-सामने

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



नई दिल्ली। दिल्ली का कांस्टीट्यूशन क्लब इन दिनों सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है। वजह है यहां होने वाला चुनाव, अक्सर कांस्टीट्यूशन क्लब में पदाधिकारियों के लिए चुनाव नहीं होते हैं। सब मिलजुल कर तय कर लेते हैं, कांस्टीट्यूशन क्लब के इतिहास में अभी तक कम ही चुनाव हुए हैं, इस बार होने वाला चुनाव चौथा चुनाव है, इससे पहले 2009, 2014, 2019 में चुनाव हुए थे। इस बार भी खेल, संस्कृति और कोषाध्यक्ष के सचिव के लिए चुनाव नहीं हुए। खेल सचिव के लिए राजीव शुक्ला, संस्कृति सचिव के लिए टी शिवा और कोषाध्यक्ष के लिए जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं। इस बार का चुनाव सचिव पद के लिए हो रहा है, जिसके लिए बीजेपी के दो नेता राजीव प्रताप रुडी और संजीव बलियान आमने-सामने हैं।

पिछले 25 साल से राजीव प्रताप रुडी ही इस क्लब के सचिव रहे हैं और यहां बहुत काम भी किया है, जिसने कांस्टीट्यूशन क्लब की सूरत ही बदल दी है। यहां के जिम को बनाने के लिए बीसीसीआई ने मदद की थी। तब शरद पवार और राजीव शुक्ला ने क्लब को एक करोड़ रूपए की मदद की थी। यहां पर आपको लोकसभा अध्यक्ष हॉल, डिप्टी स्पीकर हॉल भी है। जहां बैठकें होती हैं। इस बार का चुनाव इसलिए विशेष हो गया है क्योंकि माना जा रहा है कि संजीव बलियान को सरकार का समर्थन है जबकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल राजीव प्रताप रुडी के समर्थन में हैं।

चुनाव से पहले बिहार के नेताओं की सुरक्षा बढ़ी

» तेजस्वी यादव को जेड व पप्पू यादव को वाई श्रेणी की मिली सिक््योरिटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य के छह नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बढ़ा फेरबदल किया गया है। इसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बड़े चेहरे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भाजपा सांसद प्रदीप कुमार, और बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू की सुरक्षा को वाई प्लस स्तर पर अपग्रेड किया गया है।

वहीं जदयू के एमएलसी नीरज कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।



चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बदलाव को सियासी हलकों में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा आकलन रिपोर्ट और खतरे के स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत इन नेताओं के साथ अधिक संख्या में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी और एस्कॉर्ट वाहन तैनात रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी मौसम में नेताओं की आवाजाही, जनसभाएं और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिससे खतरे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं।

भाजपा के लिए काम कर रहा है आयोग

» दिग्विजय सिंह बोले- वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग मौन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ग्वालियर। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह देश में निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन वह एक तरह से भाजपा के अंग के रूप में काम कर रहा है। यदि भाजपा के अलावा कोई दूसरे दल का नेता धर्म के आधार पर भाषण देता है तो आयोग तुरंत नोटिस देता है, लेकिन भाजपा के नेताओं को नहीं। इसी प्रकार जब आयोग से डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट का डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन वे दे नहीं रहे हैं। वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, लेकिन आयोग की कोई जबाबदेही नहीं है और भाजपा इस पर मौन है।

दिग्विजय सिंह ने से पूछा गया कि



अगला चुनाव क्या ईवीएम के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस पर उनका कहना था कि अभी हम वोटर लिस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। वो लिस्ट चाहिए, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फार्म में हो। हर वोटर लिस्ट को स्कैन करके देश की प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा का सर्वे कर सकें। यह काम एक महीने में किया जा सकता है। कनार्टक का उदारहण सामने है, जहां एक विधानसभा के लिए सात फीट का ढेर तैयार हुआ तब जाकर हम यह काम कर सके। देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से काम करे, इसकी लड़ाई है। दिग्विजय ने

राहुल गांधी के सवालों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया हास्यास्पद : मनु सिंघवी

राज्यसभा सांसद कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य और के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल की ओर से उठाए गए सवालों पर देश की सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग शपथ पत्र पेश करने की बात कर रही है, जो हास्यास्पद नजर आती है। उन्होंने कहा कि संसद के संसदीय क्षेत्र की जहां एक या दो असेंबली में अगर ऐसा करे तो संसदीय सीट का पूरा परिणाम बदल जाता है। प्रतिपक्ष नेता कंग्रेट द्वारा चुनाव के बारे में चुनाव आयोग को लिखते हैं। इसमें जांच करके एक हफ्ते या दस दिन बाद आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा दिव्येशन आना तो दूर की बात उठा राहुल गांधी पर ही आक्रमण शुरू कर दिया गया, जोकि गलत है। आयोग को राहुल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सही से जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलतियां हैं तो उसकी जांच करके निरस्त किया जा सकता है।

कहा कि आयोग को फर्जी वोटर का मामला गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए, और यह एक गंभीर मामला है। राहुल गांधी ने पूरे प्रमाणों के साथ मामला उठाया है, जिस पर आज देश के लोग भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सही निर्णय चाहते हैं।

एशिया कप : भारतीय ओपनिंग पर असमंजस !

» चार दावेदार, सैमसन-यशस्वी और अभिषेक-गिल के बीच टक्कर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। इंग्लैंड दौरे की समाप्ती के बाद अब भारत का अगला असाइनमेंट एशिया कप है। इसकी शुरुआत नौ सितंबर से होगी और सारे मैच यूईई में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूईई के खिलाफ ही करेगी। हालांकि, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे और अब अगर ये एशिया कप के लिए खुद को उपलब्ध बताते हैं तो चयनकर्ताओं के सामने ये चुनौती होगी कि ओपनिंग के लिए किसे चुना जाए।

गिल और यशस्वी इंग्लैंड के खिलाफ



इसी साल फरवरी में खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे। गिल और यशस्वी, दोनों ने अपना-अपना पिछला टी20 मुकाबला जुलाई 2024 में पल्लेकल में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इसके बाद से किसी भी टी20 सीरीज

में ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजु सैमसन के कंधों पर रही है। इन्होंने बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली हैं, दोनों ने साथ ओपनिंग करते हुए 12 में से 10 टी20 जीते हैं। इसके अलावा सैमसन

रोहित-कोहली के वनडे भविष्य पर जल्दबाजी नहीं दिखाएगा बीसीसीआई

नई दिल्ली। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट प्रारूप से संन्यास ले लिया है और अब इन दोनों बल्लेबाजों के वनडे भविष्य को लेकर अटकलें चल रही हैं। हालांकि बीसीसीआई इन दोनों को लेकर जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं है। भारत का अगस्त में होने वाला बांग्लादेश दौरा स्थगित हो चुका है और टीम को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले इस प्रारूप की कोई सीरीज नहीं खेलनी है। कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25000 से ज्यादा रन हैं। चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे दिव्य कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जाएंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पाएंगे?

विकेटकीपर की अतिरिक्त भूमिका निभाते हैं, जबकि अभिषेक स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं।



यूपी मानसून सत्र : सपा ने योगी सरकार को घेरा

यूपी विधानसभा की हंगामे से शुरुआत, सदन में उठा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के अपमान का मुद्दा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हंगामे से हुआ। विपक्ष ने भाजपा सरकार को राज्य की समस्याओं व स्कूलों के विलय को लेकर घेरा। हंगामे को देखते हुए कई बार विधान सभा की कार्यवाही बीच-बीच में बाधित होती रही। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने नेता प्रतिपक्ष के अपमान का मुद्दा उठाया जिस पर सपा विधायकों ने उनके समर्थन में जोरदार आवाज उठाई।

सोमवार को जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि जब वह बीते दिनों गोरखपुर गए तो वहां उनके साथ अभद्रता हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जटाशंकर चौराहा, घंटाघर पर जब वह बरासत गलियारे के मुद्दे पर लोगों के बीच गए तो वहां उनके रास्ते में बुलडोजर लगाकर नारेबाजी की गई। उन्होंने मांग की कि सरकार इसकी जांच कराए। हंगामे और नारेबाजी के बीच स्पीकर सतीश महाना ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित दिया।



पिछले दिनों मुझे गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश की गई : माता प्रसाद पांडेय

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि मैं अपने नेता विधान परिषद के साथ जा रहा था तो रास्ते में ही कार्यवाही शुरू हो गई। जो पुलिस की गाड़ी आगे लगाई गई थी, वह पीछे हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश की गई।



भाजपा ने नहीं व्यापारियों ने किया था विरोध : सीएम योगी

सपा नेता के आरोप पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। आपका विरोध व्यापारियों ने किया था। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के व्यापारी आपका विरोध करते हैं, आप गोरखपुर खुद नहीं गए बल्कि अपने हाईकमान के कहने पर गए।



घटना की जांच कराई जाए

इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी मांग है कि इस घटना की जांच कराई जाए। इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा- यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इसमें जब कुछ हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की कराई जाए। इसी दौरान विपक्षी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।



विधानसभा सत्र में स्कूलों के मर्जर के खिलाफ सपा विधायक अतुल प्रधान ने कुछ इस तरह जताया विरोध।

मानसून सत्र को प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी है। मायावती ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, संक्षिप्त होने के बावजूद केवल औपचारिकता पूर्ण वाला नहीं हो, बल्कि इसको सही से प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी है, जिसके लिए सरकार एवं विपक्ष दोनों को अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ, द्वेष व कटूता आदि को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने



इस कारण जनता व देश के ज्वलंत मुद्दों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाने से लोगों में चिन्ता स्वाभाविक है। उत्तर

कहा, "इसके अलावा, संसद का जो अंगी मानसून सत्र चल रहा है उसके भी पूरी तरह शान्तिपूर्ण तरीके से नहीं चलने से वह जन अपेक्षा के अनुसार सही से कार्य नहीं कर पा रहा है।

प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "वैसे भी भारतीय व्यापार पर भारी अमेरिकी 'टैरिफ' के कारण देश की अर्थव्यवस्था व विकास पर जो बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है उसकी चर्चा व्यापक रूप से हर जगह गर्म है, जिसपर खास तौर से संसद में सही से चिन्तन-मनन करने की जरूरत है, क्योंकि यह देश के 'अच्छे दिन' से जुड़ा देशहित का खास मुद्दा है" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हलके में लेकर देश के भविष्य को दाव पर नहीं लगाया जा सकता है और सरकार व विपक्ष दोनों इस पर उचित व समुचित ध्यान दें।

सिर्फ बीजेपी नहीं विपक्षी दलों में भी बेचैनी ?

लखनऊ में सपा के हंगामे और दिल्ली में अखिलेश यादव के बैरिकेडिंग फांदने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी में सपा लगातार यह मांग कर रही है कि मानसून सत्र केवल 4 दिन का न हो और इसको बढ़ाया जाए, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आज विधानसभा के स्थगन के बाद आगे क्या फैसला होगा? अखिलेश के बैरिकेडिंग फांदने के साथ ही सपा एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया पर

सपा के नेता अखिलेश का वीडियो शेयर कर लिख रहे हैं- पीडीए ने ठाना है, एसआईआर वापस करवाना है। सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया- पीडीए मिलकर कले एसआईआर तुरंत वापस लो। दिल्ली में अखिलेश के बैरिकेडिंग फांदने से न सिर्फ बीजेपी बल्कि समूचे विपक्ष को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई है कि विरोध प्रदर्शन तो पूरे विपक्ष का था लेकिन महफिल सपा चीफ ने लूट ली।

ओह माँय गॉड, कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और कई सांसद मौत से बाल-बाल बचे

» इमरजेंसी लैंडिंग में भी लोचा, हवा में अटकी रही दो घंटे तक जान
» कांग्रेस ने कहा हादसा या साजिश, जांच की गुजारिश
» सैकड़ों यात्रियों की मौत से बस... इंच भर दूरी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ईश्वर का धन्यवाद कि एक बड़े विमान हादसे की आहत टल गयी और सभी यात्री सकुशल जमीन पर उतरने में कामयाब हुए। घटना एयर इंडिया की फ्लाइट की है बीती रात यह फ्लाइट तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही थी। इस फ्लाइट में सैकड़ों यात्रियों के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता के.सी. वेणुगोपाल भी सफर कर रहे थे। एक घंटा देरी से उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट पर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई मौसम भी ठीक नहीं था। पायलट ने फ्लाइट को तुरंत चेन्नई की ओर मोड़ दिया गया। हद तो तब हो गयी जब चेन्नई पहुंचने के बाद भी प्लेन को दो घंटे तक हवा में रूकना पड़ा।

यही नहीं लैंडिंग के संकेत मिलने के बाद जिस रनवे पर प्लेन को उतरना था वहां पहले से एक प्लेन खड़ा था। खैर हुई कि पायलट ने तुरंत प्लेन को हवा में लिया। बाद में रनवे पर खड़ा प्लेन हटाया गया और फिर प्लेन की सकुशल लैंडिंग हुई। प्लेन लैंड होने के बाद सभी यात्रियों

डरावना सफर था : वेणुगोपाल

प्लेन में बैठे कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने इस घटना को डरावना सफर बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट की। के.सी. वेणुगोपाल ने लिखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट UAI 2455 त्रिवेन्द्रम से दिल्ली जा रही थी। उसमें मैं, कई दूसरे सांसद और सैकड़ों यात्री थे। आज हम लोग बाल-बाल बच गए। यह सफर देरी से शुरू हुआ और बहुत डरावना था। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही हम खतरे में थे। लगभग एक घंटे बाद, कैप्टन ने फ्लाइट सिग्नल में खराबी की घोषणा की। प्लेन को चेन्नई की ओर मोड़ दिया गया। लगभग दो घंटे तक हम चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति का इंतजार करते रहे। इस दौरान हमारी सांसें अटकी रहीं। के.सी. वेणुगोपाल ने इस भयावह सफर के बारे में बताया कि लैंडिंग के लिए दो घंटे मंडराने के बाद प्लेन लैंड करने वाला था। हम राहत की सांस लेते कि उससे पहले एक और जान जोखिम में डालने वाली घटना हुई। प्लेन जिस रनवे पर उतरा, उस पर पहले से ही एक और प्लेन था। हालांकि कैप्टन के तुरंत लिए गए फैसले ने एक बार फिर यात्रियों की जान बचाई। कैप्टन ने प्लेन हवा में ले लिया।



ने राहत की सांस ली और कहा कि बस आज तो मरते-मरते बचे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण

देरी से उड़ा था प्लेन

प्लेन तिरुवनंतपुरम से ही एक घंटे देरी से उड़ा था और फिर चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हड़कंप मच गया। इसी प्लेन में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल समेत कई और सांसद थे। उन्होंने इस खौफनाक सफर को बर्ण किया। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2455 को तिरुवनंतपुरम से शाम 7:15 बजे उड़ान भरना था। हालांकि यह एक घंटे लेट हुई और 8:17 बजे रवाना हो सकी। फ्लाइट को दिल्ली में रात 10:45 बजे लैंड होना था, लेकिन उसे चेन्नई में लैंड किया गया।

अचानक किया गया डायवर्ट

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि 10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही फ्लाइट एआई 2455 के क्रू मेंबर्स को कुछ तकनीकी खराबी की आशंका हुई। रास्ते में मौसम भी खराब था। पायलट ने सावधानी बरतते हुए फ्लाइट को चेन्नई की ओर मोड़ दिया गया। फ्लाइट चेन्नई में सुरक्षित लैंड हुई। उसके बाद उसकी जांच की गई। एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी।

तुरंत एक्शन लिया जाए

के.सी. वेणुगोपाल ने जिम्मेदारी अफसरों और विमान को टैग करते हुए लिखा कि यात्री सुरक्षा माग्य पर निर्भर नहीं हो सकती। मैं डीजीसीए व सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे इस घटना की तत्काल जांच करें।

पर चिंता जाहिर करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है।

संघ प्रमुख भागवत ने मोदी सरकार को लगाई लताड़

» बोले भागवत- शिक्षा-इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की बढ़ती लागत और दुर्गमता पर चिंता व्यक्त की। संघ प्रमुख के इस बयान को सरकार को आइना दिखाने जैसा लिया जा रहा है। किफायती कैंसर उपचार के लिए स्थापित माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद भागवत ने कहा कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे, लेकिन आज मनुष्य की सोच ने इसे कमर्शियल बना दिया है। कैंसर उपचार सुविधाओं में अंतर पर प्रकाश डालते हुए, भागवत ने बताया कि उन्नत देखभाल केवल आठ से दस भारतीय शहरों में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज के लिए बड़ी रकम खर्च करने और लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वास्थ्य देखभाल चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। बचपन की एक घटना को याद करते हुए, भागवत ने कहा कि जब मुझे मलेरिया हुआ और मैं तीन दिनों तक स्कूल नहीं गया, तो मेरे शिक्षक मेरे इलाज के लिए जंगली जड़ी-बूटियाँ लेकर घर



आए। वह चाहते थे कि उनका छात्र स्वस्थ रहे। इस तरह की व्यक्तिगत देखभाल की समाज को फिर से जरूरत है। भागवत ने भारतीय परिस्थितियों में पश्चिमी चिकित्सा अनुसंधान को आंख मूंदकर लागू करने के प्रति भी आगाह किया और कहा कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग प्रणालियों से लाभ होता है, चाहे वह प्राकृतिक चिकित्सा हो, होम्योपैथी या एलोपैथी हो। कोई भी एक तरीका सर्वोच्च नहीं हो सकता। भारतीय चिकित्सा प्रणालियां व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर इलाज करती हैं। स्वास्थ्य सेवा की तुलना करते हुए भागवत ने कहा कि कई क्षेत्रों में छात्रों को अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूर तक यात्रा करने की जरूरत है। उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसे तकनीकी और औपचारिक शब्दों को भी खारिज कर दिया, भागवत ने कहा कि सेवा के संदर्भ में हमारे पास धर्म नामक एक शब्द है।